



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2017/आषाढ़ 28, 1939

No. 176]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2017/ ASADHA 28, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2017

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 15/06/2016-डीजीएडी: समय-समय पर यथा संशोधित, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् यहां अधिनियम भी कहा गया है) और उसके समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली भी कहा गया है) के संबंध में;

क. प्रकरण की पृष्ठभूमि

1. जहां तक उपर्युक्त अधिनियम और नियमावली का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने 04 नवंबर, 1999 की अधिसूचना संख्या 39/1/99-डीजीएडी के अनुसार चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट के विरुद्ध पाटनरोधी जांच आरंभ की थी और प्रारंभिक जांच परिणाम प्राधिकारी द्वारा 06 अप्रैल, 2000 को जारी किए गए थे। अधिसूचना संख्या 76/2000-सीमा शुल्क के अनुसार 23 मई, 2000 के अंतिम शुल्क लागू किए गए थे। प्राधिकारी ने चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट के आयातों पर निश्चित शुल्कों को लागू करने की सिफारिश करते हुए 03 नवंबर, 2000 को अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित किया। संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 147/2000 दिनांक 19 दिसंबर, 2000 के अनुसार लगाए गए थे।
2. शुल्क को लगाने की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हुए अधिसूचना संख्या 15/4/2010-डीजीएडी दिनांक 30 जून, 2011 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा द्वितीय निर्णायक समीक्षा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए गए थे। प्राधिकारी की

सिफारिशों के अनुसार, अधिसूचना संख्या 76/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 17 अगस्त, 2011 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

3. पाटनरोधी शुल्क के रूप के वर्तमान बेंचमार्क रूप से निर्धारित रूप में परिवर्तन और पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा में वृद्धि का अनुरोध करते हुए, याचिकाकर्ता की अनुनय पर आयोजित मध्यावधि पुनरीक्षा के पश्चात, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 15/2/2013-डीजीएडी, दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क के रूप में परिवर्तन की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित किया। पाटनरोधी शुल्क अधिसूचना संख्या 76/2011, दिनांक 17 अगस्त, 2011 के अनुसरण में 16 अगस्त, 2016 तक प्रवृत्त था और शुल्क की मात्रा को दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/2/2013-डीजीएडी के अनुसरण में परिशोधित किया गया था।
4. जबकि, अधिनियम और नियमावली की शर्तों में लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक कि पहले रद्द न किया गया हो, ऐसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर असर करना बंद कर देगा।
5. और, उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकारी द्वारा सीमा के समाप्त होने की तारीख से पहले उचित समयावधि के भीतर, घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए भली भांति पुष्टि किए गए अनुरोध के आधार पर पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
6. और जबकि, वर्तमान मामले में मैसर्स दीपक नाइट्रेट लि. (जिसे यहां "याचिकाकर्ता" या "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन गण (जिसे यहां संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट (जिसे यहां संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा आरंभ करने के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।
7. और जब कि निर्णायक समीक्षा जांच के आरंभ को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए अधिसूचना संख्या 15/06/2016-डीजीएडी दिनांक 27 जुलाई, 2016 के अनुसार एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है कि क्या संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तुओं के आयात पर उक्त शुल्कों की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 39/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 08 अगस्त, 2016 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों की वैधता को 16 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दिया गया है।
8. वर्तमान पुनरीक्षा के कार्यक्षेत्र में चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. कार्य विधि

9. प्राधिकारी द्वारा उक्त जांच को आरंभ करने को अधिसूचित करने वाले पब्लिक नोटिस को जारी करने के बाद, इस जांच के संबंध में नीचे बताई गई कार्य प्रणाली का अनुसरण किया गया है:
 - i. प्राधिकारी ने ऊपर नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसरण में जांच आरंभ करने की कार्रवाई से पहले पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावासों/प्राधिकारियों को अधिसूचित किया है।
 - ii. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों को जांच आरंभन अधिसूचना की एक प्रति भेजी है और उनसे जांच शुरूआत अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से परिचित कराने का अनुरोध किया है।
 - iii. प्राधिकारी द्वारा ऊपर नियमावली के नियम 6(3) के अनुसरण में भारत में संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की एक प्रति उपलब्ध कराई गई है।
 - iv. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से भी निर्धारित समय सीमा के भीतर चीन से निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया है। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्रों और प्रश्नावली की एक प्रति चीन जन गण से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पत्रों के सहित उन्हें भी भेजी गई है।
 - v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली और बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली भेजी है:
 - क. हेबेई जिंक्सिंग ब्यूरो ऑफ माइन्स
 - ख. शांक्सी जियाओचेंग होंक्सिंग केमिकल कं. लि.

- ग. शांडोंग झुचेंग झोंगताई केमिकल कं. लि.
घ. किंगदाओ हेंगुआन केमिकल्स कं. लि.
ङ. चाइना नेशनल एंड केमिकल्स आई/ई कारपो.
च. वुहान केमिकल्स आई/ई कारपो.
छ. युन्नान प्रोविंसियल केमिकल्स आई/ई
ज. जियांगमेन केमिकल्स आई/ई कंपनी ऑफ गुआंगडोंग
झ. कुनमिंग इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कारपो.
ञ. चाइना हुनान केमिकल्स इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कारपो.
ट. शांक्सी जियाओचेंग होंक्सिंग केमिकल कं. लि.
ठ. वीफांग लोंगस्टार केमिकल्स इंक.
- vi. उक्त अधिसूचना के उत्तर में, किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का न तो प्रत्युत्तर दिया है या उत्तर प्रस्तुत किए हैं।
- vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में आवश्यक जानकारी की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातकों की प्रश्नावली भेजी है:
- क. अहमदाबाद केमिकल्स, अहमदाबाद
ख. एसियाटिक इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद
ग. एरीज डाइकेम इंड., अहमदाबाद
घ. बकुल एरोमेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई
ङ. बी. आई. मेहता, मुंबई
च. कैफिल प्रा. लि., मुंबई
छ. डिटैक्स डाइकेम लिमिटेड, अहमदाबाद
ज. डायनामिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद
झ. एंजेल केम (आई) प्रा. लि., मुंबई
ञ. फार्मसन फार्मास्युटिकल्स, वडोदरा
ट. इंडोकोल केम लि., अहमदाबाद
ठ. आइसलैंड वीर केमी प्रा. लि., हैदराबाद
ड. जेनसन्स लिमिटेड, मुंबई
ढ. केटुल केम प्रा. लि., मुंबई
ण. मैट्रोकेम इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद
त. मनीष केमिकल्स, अहमदाबाद
थ. पारसिन केमिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद
द. प्रबावा एक्सपोर्ट्स, हैदराबाद
ध. रावी डाइवियर कं. लि., मुंबई
न. रोहा डाइकेम, मुंबई
प. सवाकाशी डाइ – ओ – फैब, अहमदाबाद
फ. एसयू – वीआई केमिकल्स लि., सोलापुर
ब. सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद
- viii. इस प्रकरण में संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक ने कोई प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। तथापि, संबद्ध वस्तुओं के आयातकों में से एक मै. संदीप आर्गेनिक लि. ने पाटनरोधी शुल्क को लगाने के विरोध में एक पत्र प्रस्तुत किया है।
- ix. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक खुली फाइल के रूप में, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया है।

- x. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदेवार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जिसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा के परिकलन तथा सौदों की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के डाटा का आश्रय लिया है।
- xi. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III और सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और बिक्री की लागत तथा उत्पादन की इष्टतम लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) तैयार की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में निम्न पाटनरोधी शुल्क उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xii. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसरण में मौखिक रूप से संगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर उपलब्ध कराने के लिए 27 सितंबर, 2016 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की जिसमें केवल घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। घरेलू उद्योग के जिन प्रतिनिधियों ने मौखिक सुनवाई के समय अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत किए थे, उन्हें मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप से अभिव्यक्त किए गए विचारों को लिखित प्रस्तुतियों को दायर करने की सलाह दी गई।
- xiii. निर्दिष्ट प्राधिकारी की पदस्थता में परिवर्तन तथा एटीएमए मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, 06 फरवरी, 2017 को नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक अन्य मौखिक सुनवाई आयोजित की गई जिसमें केवल घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। घरेलू उद्योग के जिन प्रतिनिधियों ने मौखिक सुनवाई के समय अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत किए थे, उन्हें मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप से अभिव्यक्त किए गए विचारों को लिखित प्रस्तुतियों को दायर करने की सलाह दी गई।
- xiv. आवश्यक सीमा तक घरेलू उद्योग के डाटा का स्थल सत्यापन किया गया। इस परिणाम के प्रयोजनार्थ, जहां भी प्रयोज्य था, आवश्यक अनुपालन संशोधन के साथ ही केवल ऐसी सत्यापित की गई सूचना का आश्रय लिया गया है।
- xv. वर्तमान पुनरीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई), अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में शामिल अवधि अप्रैल, 2012 – मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 और पीओआई है।
- xvi. इस जांच की अवधि के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का, जहां भी संगत पाया गया, प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटीकरण विवरण में उल्लेख किया गया है।
- xvii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतोषजनक पाए जाने पर, प्राधिकारी ने जहां भी जरूरत थी, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय समझा गया है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
- xviii. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान पहुँच से इंकार किया है या अन्यथा रूप से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या उल्लेखनीय रूप से जांच को बाधित किया है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणामों को दर्ज किया है।
- xix. नियमों के अनुसरण में, प्राधिकारी ने 21 जून, 2017 को हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए मामले के सभी अनिवार्य तथ्यों को सम्मिलित करते हुए एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों का, जहां तक उन्हें संगत समझा गया, इस परिणाम में उचित स्थानों पर उल्लेख किया गया है।
- xx. "****" इस दस्तावेज में हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इसी प्रकार विचार किया जाता है।
- xxi. पीओआई के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर 65.91 रुपए = 1 अमेरिकी डॉलर है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**ग.1 घरेलू उद्योग का विचार**

10. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:

- i. वर्तमान पुनरीक्षा जांच एक निर्णायक जांच है। मूल जांच और वर्तमान निर्णायक पुनरीक्षा जांच में शामिल उत्पाद सोडियम नाइट्रेट है। वर्तमान निर्णायक पुनरीक्षा में विचाराधीन उत्पाद वही समान उत्पाद है जिसे मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा धारित किया गया है। सोडियम नाइट्रेट अधिकतर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, डाई इंडस्ट्रीज, लुब्रीकेंट्स, रसायन निर्माण, रबर ब्लोइंग एजेंट, हीट ट्रांसफर साल्ट, मीट प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स आदि में प्रयोग किया जाने वाला एक सफेद क्रिस्टलीन पाउडर है।
- ii. सोडियम नाइट्रेट को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्ष 2834.10 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से संबद्ध जांच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- iii. नियोजित प्रौद्योगिकी और घरेलू व आयातित उत्पाद की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। वर्तमान जांच एक पुनरीक्षा जांच है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच, जिसका आश्रय लिया गया है, में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जांच की है।

ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. किसी भी आयातक, प्रयोक्ताओं, निर्यातकों और किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई टिप्पणी या निवेदन दायर नहीं किया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. विचाराधीन उत्पाद सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट एक ऑक्सीडाइजिंग तथा रिड्यूसिंग एजेंट है। यह फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, डाई इंडस्ट्रीज, लुब्रीकेंट्स, केमिकल्स निर्माण, रबर ब्लोइंग एजेंट, हीट ट्रांसफर साल्ट, मीट प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स आदि में अधिकतर प्रयोग होने वाला एक सफेद क्रिस्टलीन पाउडर है। संबद्ध वस्तुओं को कैटालिस्ट की उपस्थिति में उच्च तापमान पर नाइट्रस ऑक्साइड (नॉक्स गैस) से प्राप्त नाइट्रिक एसिड के प्रयोग द्वारा उत्पादित किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को बाद में सोडियम नाइट्रेट प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा/सोडा ऐश में अवशोषित किया जाता है। उत्पाद गंधहीन और जल में घुलनशील है।
13. वर्तमान जांच एक निर्णायक पुनरीक्षा जांच है और पाटनरोधी शुल्क, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पहले सिफारिश की गई थी, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर प्रवृत्त है। प्राधिकारी का विचार है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्य क्षेत्र वही बना रहा है, जैसा कि यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार, मूल और तदनुसूची पुनरीक्षा जांचों में था।
14. सोडियम नाइट्रेट को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्ष 2340.1010 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से संबद्ध जांच के कार्य क्षेत्र में बाध्यकारी नहीं है।
15. समान वस्तु के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:
"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;"
16. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने धारित किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद विचाराधीन उत्पाद से विशेषताओं की शर्तों में तुलनीय हैं, जैसे कि भौतिक और रसायन विशेषताएं, कार्य व प्रयोग, उत्पाद विशिष्टताएं, वितरण और विपणन तथा माल का टैरिफ वर्गीकरण। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। प्रयोक्ता दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।
17. इस प्रकार, प्राधिकारी ने धारित किया है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद एडी नियमों के अनुसरण में, संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का कार्य क्षेत्र और मत**घ.1 घरेलू उद्योग के विचार**

18. घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र और राय के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:

- i. याचिका को विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक के रूप में मैसर्स दीपक नाइट्रेट लि. द्वारा दायर किया गया है और मैसर्स पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लि. (भूतपूर्व पंजाब केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. या पीसीपीएल) द्वारा इसका समर्थन किया गया है। देश में उत्पाद के दो और उत्पादक हैं: नेशनल फर्टिलाइजर लि. और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड।
- ii. भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता का उत्पादन एक प्रमुख हिस्से को स्थापित करता है (पीसीपीएल द्वारा समर्थन सहित और उसके बिना दोनों) और इसलिए, याचिकाकर्ता को नियमों के अर्थों के भीतर "घरेलू उद्योग" माना जाना चाहिए।
- iii. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और इसके अतिरिक्त, यह नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर चीन में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक से या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या प्रयोक्ता से संबंधित नहीं है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. किसी भी उत्पादक/निर्यातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई निवेदन नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. आवेदन मै. दीपक नाइट्रेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया और मै. पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लि. द्वारा समर्थित था। इसके अतिरिक्त, आवेदक और समर्थनकर्ता के अलावा संबद्ध वस्तु के दो अन्य उत्पादक हैं अर्थात् नेशनल फर्टिलाइजर्स और राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.।
21. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है कि क्या (क) घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से अधिक के भाग के लिए स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन करते हैं, और (ख) आवेदन का उन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थन किया गया है जिनका सामूहिक आउटपुट घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के पचास प्रतिशत से अधिक है जो स्पष्ट रूप से आवेदन का या तो समर्थन करता है या उसके विरोध में है। आवेदक कुल घरेलू उत्पादन का 88 प्रतिशत बनाता है, और पीसीपीएल के समर्थन के साथ, आवेदक कुल भारतीय उत्पादन का 90 प्रतिशत बनाता है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या प्रयोक्ता से संबंधित नहीं है।

भारतीय उत्पादन

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
याचिकाकर्ता का उत्पादन	मी. टन	100	131	155	187
समर्थनकर्ता का उत्पादन	मी. टन	100	114	143	114
समर्थनकर्ता सहित याचिकाकर्ता	मी. टन	100	131	154	184
अन्य उत्पादकों का उत्पादन	मी. टन	100	131	155	187
कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	100	131	154	184
याचिकाकर्ता का हिस्सा	%	100	100	100	101
समर्थनकर्ता का हिस्सा	%	100	87	93	62
समर्थनकर्ता सहित याचिकाकर्ता	%	100	100	100	100
अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	100	100	100	101
कुल	%	100	100	100	100

22. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और उचित जांच के बाद प्राधिकारी ने धारित किया है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के तहत घरेलू उद्योग है।

ड. बाजार अर्थव्यवस्था उपचार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण नियमावली के तहत सामान्य मूल्य

23. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" से तात्पर्य है:

व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र में उपभोग के लिए नियत हो, अथवा

जब निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:—

समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग अन्य के साथ-साथ निम्नानुसार निवेदन करता है:

- क. परिग्रहण प्रोटोकॉल के प्रावधानों में से एक प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है। प्राधिकारी को नीचे दिए गए कारणों से और गैर बाजार आर्थिक स्थितियों में प्रचालन कर रहे उत्पादकों के रूप में चीनी उत्पादकों पर विचार करते हुए वर्तमान जांच को आगे बढ़ाना चाहिए।
- ख. वर्तमान मामले में प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच की अवधि अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 (12 महीने) है। क्षति जांच की अवधि को 2012-13, 2013-14, 2014-15 और पीओआई की अवधि के रूप में समझा गया है।
- ग. पीओआई को निर्धारित करने का प्रयोजन ऐसी अवधि पर विचार करना है, जब क्षति करने वाले पाटन की मौजूदगी का दावा किया जाता है और स्थापित किया जाता है। निर्धारण की तारीख घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले पाटन के विवादास्पद पक्ष से संगत नहीं है। चूंकि, घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले पाटन का तथ्य जांच अवधि के आधार पर स्थापित है, जांच की अवधि के दौरान अभिभावी स्थितियों को अकेले ही इस प्रयोजन के लिए संगत, उचित और आवश्यक समझा जाना चाहिए।
- घ. चीनी उत्पादकों को इस कारण गैर विपणन आर्थिक कंपनियों के रूप में माने जाने की आवश्यकता है कि चीन में लागत और कीमतें सही ढंग से बाजार शक्तियों को नहीं दर्शातीं। अनुबंध-I का पैरा 8 उन पैरामीटरों को विनिर्दिष्ट करता है जिन पर बाजार अर्थव्यवस्था प्रास्थिति प्रदान करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। यह भी अंतर्निहित करता है कि जब तक इन स्थितियों को पूरा/संतुष्ट नहीं किया जाता, चीनी लागतों और कीमतों को अपनाया नहीं जा सकता।
- ड. बाजार अर्थव्यवस्था प्रास्थिति का विचार जांच की अवधि के दौरान प्रभावी पैरामीटरों पर आधारित है। चूंकि, चीनी कीमतों और लागतों की अस्वीकृति का कारण अनुबंध-I के पैरा 8 में सूचीबद्ध कारकों के कारण चीन में लागत और कीमतों में विरुपण है, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि यह जांच अवधि है जो चीनी उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था कंपनियों के रूप में समझने के निर्णय को संगत बनाती है।
- च. चूंकि, चीनी कंपनियों ने दिसंबर, 2016 तक अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित कारणों से बाजार अर्थव्यवस्था प्रास्थिति से इंकार किया है, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि चीनी उत्पादकों को ऐसे समय तक गैर बाजार अर्थव्यवस्था कंपनियों के रूप में माने जाने की जरूरत है, जब तक जांच की अवधि में परिग्रहण संधि प्रोटोकॉल में विनिर्दिष्ट अवधि शामिल है।
- छ. नियम 2(ख) के संदर्भ में, यह एक कानूनी रूप से स्थापित कानूनी स्थिति है कि किसी घरेलू उत्पादक द्वारा किए गए आयात या किसी निर्यातक या आयातक के साथ उसके संबंधों की जांच की अवधि के संदर्भ में जांच की जाती है। यदि सिर्फ पीओआई स्थायी प्रयोजनों के लिए संगत है तो सिर्फ पीओआई को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए संगत होना चाहिए।
- ज. चीनी उत्पादकों को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वातावरण के तहत प्रचालन करने वाली कंपनियों के रूप में माने जाने की आवश्यकता है और प्राधिकारी को अनुबंध-I के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण को आगे बढ़ाना चाहिए।

- झ. सामान्य मूल्य को किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर इस कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता कि संगत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता ने भारत में भली भांति समायोजित उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने का दावा किया है।
- ञ. चीन से पाटन मार्जिन न केवल उल्लेखनीय है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है और इस प्रकार भारत में विचाराधीन उत्पादन के उल्लेखनीय पाटन की उपस्थिति को स्थापित करता है। प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के बावजूद वर्तमान सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान चीन की आयात मात्रा उल्लेखनीय बनी रही है।
- ट. चीनी उत्पादकों के पास उपलब्ध उत्पादन क्षमता और उनके उच्च निर्यात प्रचालन को देखते हुए हुए पाटन जारी रहेगा और पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में यह और अधिक बढ़ जाएगा।

ड. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. किसी भी आयातक, प्रयोक्ता, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई निवेदन नहीं किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रभावी रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक

विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

27. अनुच्छेद 15 लागू करता है कि उप पैराग्राफों में से एक के प्रावधान चीन के परिग्रहण की तारीख से 15 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस पैराग्राफ के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए थे। चूंकि, घरेलू उद्योग को क्षति करने वाले पाटन के तथ्य जांच की अवधि पर आधारित है, जांच की अवधि के दौरान अभिभावी स्थितियां वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संगत, उचित और अनिवार्य हैं। वर्तमान पुनरीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 है। चूंकि, जांच की अवधि के दौरान अनुच्छेद 15 का उप पैराग्राफ अस्तित्व में था, प्राधिकारी ऐसे विधि तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ कड़ी तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा सकते कि उस उत्पादन के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां प्रचलित हैं।
28. प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि पिछले तीन वर्षों में भारत और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांच में चीन जन गण को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश माना गया है। नियमों की शर्तों में निर्यातक देश या वैयक्तिक निर्यातक द्वारा परिकल्पना के खंडन के अध्यक्षीन चीन जन गण को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश माना गया है।

इ.3.1 बाजार अर्थव्यवस्था दावों की जांच

29. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" परिकल्पना का खंडन किया जा सकता है कि यदि चीन जन गण से निर्यातक पैरा 8 के उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड के आधार पर पर्याप्त सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और तथ्यों को विपरीत रूप से स्थापित करता है। चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी की निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रश्नावली के उत्तर में पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित अनिवार्य सूचना/पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता है कि क्या:
- (क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है;
 - (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;
 - (ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है:-
 - (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं।

30. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है और प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किए हैं। उपर्युक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और किसी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर बाजार अर्थव्यवस्था परिकल्पना के खंड की अनुपस्थिति में और चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुच्छेद-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में चीन जन गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश मानना उचित समझा है।

इ.3.2. चीन जन गण में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

31. भारत में चीन जन गण से आयातित संबद्ध उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग के लिए अनुमोदित स्तरों पर प्रमुख कच्ची सामग्री और यूटिलिटीज, प्रमुख कच्ची सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों (कास्टिक सोडा और अमोनिया), परिवर्तन प्रभार, व्याज, एसजीए आदि के लिए घरेलू उद्योग के इष्टतम उपभोक्ता मानदंडों पर विचार करते हुए निर्मित किया गया है। डीजीएडी पद्धति के अनुसार, व्याज के बिना बिक्री की लागत का 5 प्रतिशत उचित लाभ के लिए स्वीकृत है।

इ.3.3. निर्यात कीमतों का निर्धारण

32. संबद्ध देश से किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत का विवरण देते हुए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। अतः प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के सौदेवार डाटा के आधार पर चीन जन गण के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार, चीन जन गण से सभी निर्यातकों के संबंध में, एक्स फैक्ट्री स्तर पर भारांशित औसत निवल निर्यात कीमत को

उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय माल भाड़ा प्रभारों के लिए देय समायोजन किए जाने के बाद निर्धारित किया गया है और पाटन मार्जिन सारणी में इसका उल्लेख किया गया है।

ड.3.4. पाटन मार्जिन का निर्धारण

33. पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए भारत की निर्यात कीमत (प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सभी समायोजनों को घटाकर) की सामान्य मूल्य के साथ तुलना की गई है। संबद्ध देश से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पीओआई के दौरान पाटन मार्जिन को नीचे दी गई सारणी में उपलब्ध कराए गए अनुसार निर्धारित किया गया है:

पाटन मार्जिन

विवरण	यूनिट	पीओआई
सामान्य मूल्य	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
निवल निर्यात कीमत	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
पाटन मार्जिन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन	रेंज	30-40

च. क्षति और कारणात्मक संबंध

च.1. घरेलू उद्योग के विचार

34. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में, घरेलू उद्योग के अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:

- संबद्ध वस्तुओं की मांग/प्रत्यक्ष खपत में पीओआई की क्षति अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध देश से आयात उल्लेखनीय बने रहे हैं, कुल रूप में और भारत में उत्पादन/उपभोग दोनों के संबंध में।
- आयातों की भूमि उतरान कीमत (आधारभूत सीमा शुल्क शुल्कों को शामिल करने के बाद) में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से महत्वपूर्ण रूप से कम है। परिस्थितियों के अंतर्गत, पाटनरोधी शुल्क के समाप्त हो जाने पर, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में और अधिक कटौती होगी जो महत्वपूर्ण सीमा तक कीमत में वृद्धि को रोकेंगा।
- चीन से आयातों की भूमि उतरान कीमत घरेलू उद्योग की कीमत से महत्वपूर्ण रूप से कम है।
- संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप गिरावट आई है। हालांकि, संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा अभी भी उल्लेखनीय है।
- घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। क्षमता में यह वृद्धि देश में उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग को देखते हुए पूरी तरह से औचित्यपूर्ण थी। क्षति अवधि की तुलना में घरेलू बिक्री की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।
- तथापि, कीमत में कटौती के स्तर को ध्यान में रखते हुए, यह साक्ष्य है कि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में आयातित उत्पाद की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह घरेलू उत्पाद की मांग में गिरावट को प्रत्यक्ष रूप से शामिल करेगा, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है।
- कीमत मानदंडों की शर्तों में घरेलू उद्योग के निष्पादन जैसे लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर लाभ ने भी पीओआई में सुधार दर्शाया है। घरेलू उद्योग वित्तीय हानियों की स्थिति से बाहर आया है और संदर्भित कीमत आधार से निर्धारित रूप से पाटनरोधी शुल्क के फार्म में संशोधन के पश्चात सांकेतिक लाभ प्राप्त कर रहा है।
- पाटनरोधी शुल्क की अनुपस्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति के कारण महत्वपूर्ण पाटित आयातों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप पाटन जारी रहेगा।
- वर्तमान पीओआई में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक और महत्वपूर्ण हैं।
- संबद्ध देश में निर्यातकों की क्षमता और उनकी निर्यात प्रचालन पर विचार करते हुए, वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की अनुमति देने की स्थिति में, आयात के और अधिक गहन होने की संभावना है।

- xi. परिणामस्वरूप, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति का सामना किए जाने की संभावना है।
- xii. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है। उपाय के रूप को अमेरिकी डॉलर की शर्तों में निश्चित मात्रा के रूप में रखे जाने की जरूरत है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

35. कोई सहयोगी निर्यातक या आयातक नहीं हैं। तथापि, जांच का विरोध करते हुए एक हितबद्ध पक्षकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस पक्षकार द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:

- i. आयात कीमतें प्रत्यक्ष रूप से कच्चे माल, मुद्रा और माल भाड़े से संबंधित हैं,
- ii. चीन से आयातों में कमी आई है,
- iii. रक्षोपाय शुल्क भी मौजूद हैं,
- iv. घरेलू उत्पादकों के बीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा है,
- v. मांग कम है
- vi. घरेलू उद्योग उत्पादन की उच्च कीमत का सामना करते हैं,
- vii. घरेलू उद्योग लाभ प्राप्त कर रहे हैं,
- viii. घरेलू उद्योग सरकारी सब्सिडी प्राप्त करते हैं,
- ix. आयात शुल्क उच्चतर हैं,
- x. मुद्रा की वर्तमान विनिमय दर उच्चतर है,
- xi. पुराने शुल्कों पर फिर से काम किया जाना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को प्राधिकारी ने ध्यान में रखा है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की उचित रूप से जांच की है।
- 37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभिप्राय के संबंध में कि उत्पाद की आयात कीमत प्रत्यक्ष रूप से कच्चे माल, करेंसी और माल भाड़े से संबंधित है, प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि उत्पाद की कीमत निर्धारण का किसी भी प्रकार कच्ची कीमत से कोई संबंध नहीं है। करेंसी की विनिमय दर में उतार चढ़ाव एक सामान्य घटना है, उत्पाद विशिष्ट नहीं और माल भाड़ा भी मुद्रास्फीति कारक प्रभावों से नियंत्रित होता है।
- 38. जहां तक संबद्ध वस्तुओं के आयात पर रक्षोपाय शुल्क की उपस्थिति का संबंध है, प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि अधिसूचना संख्या 01/2014-सीमा शुल्क (एसजी) दिनांक 26 फरवरी, 2014 के अनुसार लगा रक्षोपाय शुल्क पहले ही 25 मई, 2015 को समाप्त हो चुका है और इस समय कोई रक्षोपाय शुल्क प्रवृत्त नहीं है।
- 39. यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अन्य निवेदनों का उल्लेख करता है।
- 40. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ... "ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"
- 41. विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों

के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या पाटित आयातों से भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अथवा स्वतंत्र रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक हो गई होती।

42. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II का पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लिखित है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल होगा, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर लाभ या क्षमता के उपयोग में प्राकृतिक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी के प्रवाह पर संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"

43. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में समाप्त न किया गया हो, का इस प्रकार के अधिरोपण की तिथि से 5 वर्षों के समाप्त होने पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार किसी समीक्षा में इस मत पर पहुँचती है कि इस प्रकार के शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना है, यह समय-समय पर इस प्रकार के अधिरोपण की अवधि को 5 वर्षों की एक अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकती है और इस प्रकार की अतिरिक्त अवधि इस प्रकार के विस्तार के आदेश की तिथि से शुरू होगी।
44. भारत में घरेलू उद्योगों पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध-II (iv) के अनुसार, इस प्रकार के सूचकांकों पर विचार किया है जिसका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि।
45. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने की कार्रवाई करते हैं।

च.3.1 पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

क) मांग और बाजार हिस्सा

46. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को सभी स्रोतों से आयातों और भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

मांग और बाजार हिस्सा

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन - सूचीबद्ध	100	136	159	194
घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत	मी. टन - सूचीबद्ध	100	110	92	131
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. टन - सूचीबद्ध	100	127	152	168
संबद्ध देश – चीन जन गण	मी. टन - सूचीबद्ध	18,510	14,971	11,432	12,688
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता हो – यूरोपीय संघ	मी. टन - सूचीबद्ध	3,508	1,561	1,706	1,869
अन्य देश	मी. टन - सूचीबद्ध	-	-	-	213
कैप्टिव सहित मांग	मी. टन - सूचीबद्ध	100	108	112	134
कैप्टिव को छोड़कर मांग	मी. टन - सूचीबद्ध	100	107	113	134
कैप्टिव सहित मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	% - सूचीबद्ध	100	127	142	146

घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत	% - सूचीबद्ध	100	103	82	98
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	% - सूचीबद्ध	100	118	135	125
संबद्ध देश - चीन जन गण	% - सूचीबद्ध	100	75	55	51
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता हो - यूरोपीय संघ	% - सूचीबद्ध	100	41	43	40
अन्य देश	% - सूचीबद्ध	-	-	-	100

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत को शामिल करते हुए तथा बाहर करते हुए, दोनों के लिए पूर्व वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
48. यह नोट किया गया है कि घरेलू खपत को शामिल करते हुए और उसे बाहर रखते हुए, दोनों स्थिति में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ा है जबकि संबद्ध देश के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। हालांकि, यह अभी भी बहुत अधिक है। यूरोपीय संघ, जिस पर पाटनरोधी शुल्क भी लगता है, से आयातों के बाजार हिस्से में 2013-14 से गिरावट आई है और यह बहुत कम है।

ख) संबद्ध देश की आयात की मात्रा और हिस्सा

49. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस पर विचार करे कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अथवा स्वतंत्र रूप में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया है:

आयात एवं बाजार हिस्सा

आयात मात्रा	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
संबद्ध देश - चीन	मी. टन	18,510	14,971	11,432	12,688
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता हो - यूरोपीय संघ	मी. टन	3,508	1,561	1,706	1,869
अन्य देश	मी. टन	-	-	-	213
कुल आयात	मी. टन	22,018	16,532	13,138	14,770
आयात में बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश - चीन	%	84.07	90.56	87.02	85.90
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता हो - यूरोपीय संघ	%	15.93	9.44	12.98	12.65
अन्य	%	-	-	-	1.44
कुल आयात	%	100.00	100.00	100.00	100.00
उत्पादन	मी. टन - सूचीबद्ध	100	131	154	184
कैप्टिव सहित मांग	मी. टन - सूचीबद्ध	100	108	112	134
की तुलना में आयात -					
उत्पादन	% - सूचीबद्ध	100	62	40	37
कैप्टिव सहित खपत	% - सूचीबद्ध	100	75	55	51

50. यह नोट किया गया है कि चीन से आयात की मात्रा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के बावजूद क्षति की पूरी अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में बहुत अधिक रही है। यद्यपि, भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है; यह अभी भी बहुत अधिक है।

च3.2 पाटित आयातों की कीमत का प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

क) कीमत में कटौती

51. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस पर विचार करे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के

आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में कीमतों पर दबाव पड़ता अथवा कीमतों में वृद्धि रुक जाती जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। इस संबंध में, घरेलू उद्योग की औसत बिक्री, जिसमें व्यापार के उसी स्तर पर सभी प्रकार की छूट एवं कर की निवल कीमत के साथ इस उत्पाद के पहुँच मूल्य के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया है।

52. कीमत में कटौती का आकलन आयात के पहुँच मूल्य की तुलना भारत में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमत से करते हुए की गई है। यह देखा जाएगा कि बिना पाटनरोधी शुल्क के आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की अपेक्षा में कम है और इससे यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाए तब नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार कीमत में पर्याप्त कटौती होगी:

कीमत में कटौती

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
आयात की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	29,501	30,835	31,213	31,596
निवल बिक्री कीमत	रु./मी. टन - सूचीबद्ध	****	****	****	****
कीमत में कटौती	रु./मी. टन - सूचीबद्ध	****	****	****	****
कीमत में कटौती	% - सूचीबद्ध	****	****	****	****
कीमत में कटौती	रेंज	5-25%	5-25%	5-25%	5-25%

ख) कम कीमत पर बिक्री

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया गया है और उसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा तक पहुँचने के लिए संबद्ध वस्तुओं के पहुँच मूल्य से की गई है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए किया गया है।

कम कीमत पर बिक्री

विवरण	रु./मी. टन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन
परिवर्तन दर		65.91
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	***	***
पहुँच कीमत	***	***
क्षति मार्जिन	***	***
क्षति मार्जिन-%	***	***
क्षति मार्जिन (रेंज)	10-20	10-20

54. यह देखा गया है कि चीन से संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना में बहुत कम है।
- ग) **पाटित आयातों का कीमत पर दबाव एवं न्यूनीकरण संबंधी प्रभाव**
55. यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा न्यूनीकरण हो रहा है तथा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव डालता अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकता जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक हुआ होता, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया है। यह स्थिति नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शाई गई है:

कीमत दबाव/न्यूनीकरण

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	96	94
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	112	116
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	29,501	30,835	31,213	31,596
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	105	106	107

56. यह देखा गया है कि:

- आयातों की पहुँच कीमत जांच की अवधि सहित क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है।
- आयातों की पहुँच कीमत जांच की अवधि सहित क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से बहुत कम है।
- जांच की अवधि में कीमत पर कोई दबाव अथवा न्यूनीकरण संबंधी प्रभाव नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क के न होने के कारण, संबद्ध आयातों से घरेलू कीमतों में गिरावट होगी जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन और बदतर हो जाएगा।

च3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंडों की जांच

57. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल रहेगी। इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में इसके अलावा यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का एक वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर लाभ या क्षमता के उपयोग में प्राकृतिक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी के प्रवाह पर संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।

58. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण नीचे किया गया है:

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

59. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
क्षमता संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	135	146	161
उत्पादन - संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	126	150	175
उत्पादन - विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचकांक	100	131	155	187
उत्पादन - एसएनए	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	111	134	139
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	93	102	109
कैप्टिव खपत को छोड़कर घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	136	159	194
कैप्टिव खपत सहित घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	134	153	189
कैप्टिव सहित कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	108	112	134

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान पाटन क्षमता में वृद्धि की है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि क्षमता में इस प्रकार की वृद्धि देश में इस उत्पाद के लिए वर्तमान और संभावित मांग द्वारा पूर्ण रूप से न्यायोचित है।
- घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री की मात्रा में भी क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप आयात किए जाने वाले उत्पाद के आयात में वृद्धि होगी। इसका प्रत्यक्ष तौर पर यह मतलब होगा कि घरेलू उद्योग के उत्पाद की मांग में गिरावट आएगी जिसके फलस्वरूप संभवतः घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आएगी।

ख) बाजार हिस्सा

61. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच नीचे दिए गए अनुसार गई है:

मांग में बाजार हिस्सा

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
कैप्टिव सहित मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	% - सूचीबद्ध	100	127	142	146
घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत	% - सूचीबद्ध	100	103	82	98
अन्य भारतीय उत्पादक	% - सूचीबद्ध	100	118	135	125
संबद्ध देश - चीन जन गण	% - सूचीबद्ध	100	75	55	51
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता हो - यूरोपीय संघ	% - सूचीबद्ध	100	41	43	40
अन्य देश	% - सूचीबद्ध	-	-	-	100

62. यह नोट किया गया है कि कैप्टिव खपत को शामिल करते हुए तथा उसे बाहर करते हुए, दोनों स्थितियों में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है; जबकि संबद्ध देश के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। हालांकि, यह अभी भी बहुत अधिक है। यूरोपीय संघ, जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, से आयातों के बाजार हिस्से में 2013-14 से गिरावट आई है और यह बहुत कम है।

ग) **मालसूची**

63. नीचे दी गई सूचना से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के औसत मालसूची स्तर में वर्ष 2014-15 में बहुत अधिक गिरावट आई है और तब जांच की अवधि में पुनः वृद्धि हुई है।

मालसूची

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	27	53

घ) **लाभ, निवेश पर आय और नकदी का प्रवाह**

64. लाभ, निवेश पर आय और नकदी के प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	96	94
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	112	116
लाभ/हानि	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(66)	(11)	26
लाभ/हानि	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(91)	(18)	51
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(81)	13	104
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(80)	15	101
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(32)	5	31

65. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण 2014-15 तक घाटा हो रहा था। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में कुछ मामूली लाभ दर्ज किए हैं। इसी प्रकार से, ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय जांच की अवधि में सकारात्मक रहे हैं, परंतु नियोजित पूंजी पर आय 22 प्रतिशत की निर्धारित आय से बहुत अधिक कम रही है।

ड) उत्पादकता

66. नीचे दी गई सूचना से, प्रति दिन उत्पादकता तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता के मामले में क्षति की अवधि के दौरान उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जो उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप है:

उत्पादकता

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	126	151	177
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	131	155	187

च) रोजगार एवं मजदूरी

67. नीचे दी गई तालिका से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास रोजगार क्षति की अवधि के दौरान बढ़ा है। हालांकि, इसमें 2014-15 में गिरावट आई थी। भुगतान की गई मजदूरी में भी 2013-14 में गिरावट को छोड़कर वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये मानदंड अनेक अन्य मानदंडों पर निर्भर करते हैं और यह घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव को नहीं दर्शाता है।

रोजगार एवं मजदूरी

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	104	102	106
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	66	209	263

छ) वृद्धि

68. नीचे दी गई तालिका दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत, दोनों मानदंडों जैसे बिक्री की मात्रा, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर आय, नकद लाभ आदि के मामले में पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के प्रभाव के रूप में क्षति की अवधि में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

वृद्धि

वृद्धि % (वर्ष दर वर्ष)	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
उत्पादन	मी. टन	-	***	***	***
घरेलू बिक्री	मी. टन	-	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	-	***	***	***
बाजार हिस्सा	%	-	***	***	***
प्रति यूनिट लाभ/हानि	रु./मी. टन	-	***	***	***
नकद लाभ	रु. लाख	-	***	***	***
निवेश पर लाभ	%	-	***	***	***

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

69. घरेलू उद्योग ने देश में इस उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग पर विचार करते हुए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि की है। हालांकि, पाटन जारी रहा है और यह पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की पूंजी जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

झ) पाटन एवं पाटन मार्जिन का स्तर

70. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से आयात इस देश में पाटित कीमतों पर हो रहा है और यह कि पाटन का मार्जिन अधिक है।

ञ) घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक

71. जांच की अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक एवं बहुत अधिक हैं। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन ने उत्पादन और बिक्री की मात्रा के मामले में सुधार दर्शाया है। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन ने कीमत के मानदंडों के मामले में भी सुधार दर्शाया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में कुछ लाभ अर्जित किए हैं।

ट. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

72. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत, सूचीबद्ध अन्य कारकों की जांच की है जिसने घरेलू उद्योग को पाटन और पर्याप्त क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच के लिए घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान किया होगा।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ से इस देश में हो रहे आयातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लगता है। अन्य सभी देशों से आयात मामूली हैं और इससे घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति नहीं हो सकती थी।

ख) मांग में संकुचन

74. क्षति की अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती थी।

ग) मांग के पैटर्न में परिवर्तन

75. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कारण से खपत के पैटर्न में परिवर्तन को घरेलू उद्योग को क्षति करने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

घ) प्रौद्योगिकी का विकास

76. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से प्रौद्योगिकी में विकास को एक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई हो।

ड) प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ एवं व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

77. कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुँची हो।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

78. घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन और उसमें क्षति की जांच संभव सीमा तक घरेलू कार्य निष्पादन के संबंध में की गई है। इस कारण से घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण हो सकता है।

छ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचे गए अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

79. घरेलू उद्योग द्वारा जिन अन्य उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है और जिन्हें बेचा जा रहा है, उनके कार्य निष्पादन ने घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के बारे में प्राधिकारी द्वारा किए गए आकलन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है। प्राधिकारी द्वारा विचार की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

ज) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता ने उसी प्रवृत्ति को अपनाया है जो उत्पादन का था और इस प्रकार में इसमें वृद्धि हुई है। उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

81. ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर में सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने निर्धारित क्षति नहीं पहुँचाई है। क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने के फलस्वरूप सुधार हुआ है। हालांकि, संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर आयातों की बहुत अधिक मात्रा इस देश में आना जारी है।

ज) पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना

82. प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का मुख्य केंद्र, यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया गया, यद्यपि वर्तमान में कोई क्षति नहीं हो रही है, फिर भी सतत पाटन एवं परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना है। यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयात घरेलू बाजार में पाटित एवं क्षतिकारक कीमत पर अभी भी हो रहे हैं।

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

83. घरेलू उद्योग ने पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना के अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए अनुसार अनुरोध किया है:

- i. जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त पाटन मार्जिन इस बात को सिद्ध करता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने और उसके अधिक होने की संभावना है। समग्र जांच की अवधि के दौरान पाटन हुआ। इसके अलावा, उच्च पाटन मार्जिन पूर्व की पाटन मार्जिन जांचों के दौरान हुआ था। यह स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष तक ले जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की प्रत्येक संभावना है।
- ii. पाटनरोधी एवं सब्सिडीरोधी उपाय संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संबद्ध वस्तुओं के निर्यात पर लागू हैं। इस देश में सूचित किए गए आयातों की मात्रा में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाटनरोधी एवं सब्सिडीरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात वृद्धि हुई।
- iii. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर भारत में किया जाना जारी है।
- iv. संबद्ध देश के उत्पादकों के पास पर्याप्त क्षमता है जो यह सिद्ध करता है कि शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में निर्यात और अधिक हो जाएगा।
- v. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भारत तथा तीसरे देशों, दोनों में बहुत अधिक हुआ है। इसके अलावा, निर्यात की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है।
- vi. वर्तमान जांच की अवधि में, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, दोनों सकारात्मक और पर्याप्त हैं।
- vii. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत में कटौती सकारात्मक है। निवेश पर आय और नकद लाभ पाटनरोधी शुल्क के हटाए जाने की स्थिति में बहुत अधिक नकारात्मक होंगे।
- viii. आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत अधिक कम हैं। इस कारण से ग्राहक पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयात किए गए उत्पाद को अपनाएंगे जिससे इस उत्पाद के आयात में बहुत अधिक वृद्धि होगी। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए अपनी बिक्री कीमत में कटौती करनी होगी जिससे वे बिक्री की लागत से कम पर भी बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसके फलस्वरूप कीमत में बहुत अधिक क्षति होगी।
- ix. विदेशी उत्पादक का गहन रूप से ध्यान निर्यात पर होता है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, ये निर्यातक संभवतः पाटित कीमतों पर भारत में अपने निर्यात में वृद्धि करना चाहेंगे।
- x. भारतीय बाजार कीमत के मामले में बहुत संवेदनशील है। ग्राहक कीमत पर सबसे अधिक ध्यान देते हुए अपनी खरीद के बारे में निर्णय लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति होने के कारण, बाजार में संबद्ध देश से कम कीमत पर आयातों की उपलब्धता से घरेलू उद्योग की कीमतों पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए घरेलू उद्योग को पाटन एवं परिणामी क्षति पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में जारी रहने/उसमें वृद्धि होने की संभावना है।

ज.2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

84. किसी भी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

85. प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-II (vii) के संबंध में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना की जांच की है। इस नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में चार कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है अर्थात:

(क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

86. पूर्व जांचों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन और अब आकलन किए गए पाटन मार्जिन पर विचार करते हुए यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि पाटित कीमतों पर निर्यात किया जाना जारी था और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के साथ इसके जारी रहने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात पाटित कीमतों पर अब भी जारी है। इसके अलावा, पाटित आयातों की मात्रा चीन जन गण से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से कीमत में कटौती के प्रभावों के स्तर को देखते हुए पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में और अधिक बढ़ जाने की संभावना है।

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

87. वास्तविक क्षति के खतरे की जांच करने के लिए इस मानदंड में भारतीय बाजार में निपटान योग्य मात्रा को परिवर्तित किए जाने की संभावना को तलाश करने के लिए मौजूदा अतिरिक्त क्षमताओं और क्षमता वर्धन, यदि कोई हो, का मूल्यांकन अपेक्षित है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों को पहले से ही बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, ये उत्पादक इस उत्पाद का निर्यात अनेक देशों में कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के संबंध में कीमतों से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है और इस प्रकार से पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने की स्थिति में भारत में इन निर्यातों को परिवर्तित किए जाने की संभावना दृष्टिगत होती है। हितबद्ध पक्षकारों ने मौजूदा अतिरिक्त क्षमताओं और भारतीय बाजार में बढ़े हुए पाटित निर्यातों की परिणामी संभावना के संबंध में सत्यापन योग्य कोई साक्ष्य और सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है

88. वे कीमत, जिस पर संबद्ध वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, उस कीमत की तुलना में बहुत कम है जिस पर इन वस्तुओं को भारत में बेचा जा रहा है। इस कारण से शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, संबद्ध देश से निर्यातक उनके पास बहुत अधिक क्षमता को देखते हुए भारतीय बाजार में अपना उत्पादन भेजेंगे। इससे स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना रहेगी। संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होने की संभावना है।

(घ) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो।

89. घरेलू उद्योग की मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में कमी आई है।

झ. क्षति एवं क्षति मार्जिन की मात्रा

90. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति के मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से इन आयातों के पहुँच मूल्य से की गई है और इस प्रकार से निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दिया गया है:

क्षति मार्जिन

विवरण	अमेरिकी डॉलर/मी. टन
परिवर्तन दर	65.91
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	***
पहुँच कीमत	***
क्षति मार्जिन	***
क्षति मार्जिन-%	***
क्षति मार्जिन (रेंज)	10-20

ज. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां:

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

91. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुरोध किया है:

क. विचाराधीन उत्पाद सोडियम नाइट्रेट है। चूंकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी शुल्क तालिका में कृपया उसका उल्लेख करें और यह कि विचाराधीन उत्पाद पर सीमा शुल्क वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत इन वस्तुओं का निपटारा आयातकों द्वारा किया जा रहा है, पर विचार किए बिना शुल्क लगेगा।

ख. जांच की अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, दोनों सकारात्मक हैं।

- ग. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन ने पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से अधिरोपित किए जाने के फलस्वरूप तथा बैचमार्क से निर्धारित रूप में पाटनरोधी शुल्क के रूप में परिवर्तन के कारण मात्रा तथा कीमत मानदंडों के संबंध में सुधार दर्शाया है।
- घ. घरेलू उद्योग को सतत क्षति नहीं हुई है लेकिन पाटन जारी रहा है।
- ङ. गहन पाटन एवं परिणामी क्षति की संभावना आसन्न है क्योंकि बहुत अधिक पाटन प्राधिकारी द्वारा पूर्व की जांचों में पाया गया था, आयातों की मात्रा प्रारंभ से तथा वर्तमान जांचों में भी बहुत अधिक रही है, चीन के उत्पादकों के पास भारत में मांग की तुलना में बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताएं हैं, चीन के उत्पाद पर संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबे समय से पाटनरोधी और सब्सिडीरोधी शुल्क लगता रहा है, अन्य देशों में निर्यात पाटित एवं क्षतिकारक कीमतों पर हो रहे हैं।
- च. चूंकि भारतीय बाजार कीमत के मामले में अत्यधिक संवेदनशील है, अतः पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप भारतीय बाजार में पाटित वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में आएंगी जिसके कारण घरेलू कीमतों में कटौती होगी और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।
- छ. जबकि याचिकाकर्ता अनुबंध-III की अपेक्षा से ही सहमत नहीं है, अतः बिना किसी पूर्वाग्रह के कम से कम प्राधिकारी इस नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार क्षति रहित कीमत का कृपया फिर से निर्धारण करें।
- ज. प्राधिकारी कृपया मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार पर भी विचार करें क्योंकि कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। क्षति नहीं होने का आशय यह है कि क्षति मार्जिन की गणना अपेक्षित नहीं है और वही शुल्क लगाया जाना चाहिए।
- झ. पाटनरोधी शुल्क अमेरिकी डॉलर में व्यक्त मौजूदा मात्रा और निर्धारित रूप में जारी रखा जाना चाहिए।

ब.2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

92. किसी भी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध/प्रकटन पश्चात टिप्पणियां अधिकांशतः पूर्व में किए गए अनुरोध की पुनरावृत्ति ही है जिसकी उपयुक्त रूप से जांच पहले ही की जा चुकी है और उसका समुचित समाधान वर्तमान जांच परिणाम के प्रकटन विवरण अथवा संगत पैराओं में किया जा चुका है। इसके अलावा, प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए नए मुद्दों के संबंध में नीचे दिए गए अनुसार विचार करते हैं:

- i. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत की गणना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में दिए गए हैं और वर्तमान जांच में क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय उसको अपनाया गया है।
- ii. शुल्क की मौजूदा मात्रा और रूप को जारी रखने के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध का जहां तक प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन सकारात्मक हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी का अधिकार कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करना और पाटनरोधी शुल्क की समुचित मात्रा की सिफारिश करना है जिसके लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को क्षति समुचित रूप से दूर किया जा सके। तदनुसार, पाटनरोधी उपायों की मात्रा और रूप के बारे में निर्णय किसी मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद लिया जाता है।

ट. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों के अधिरोपण से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश/क्षेत्र से आयात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से यह उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
95. यह मान लिया गया है कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद के सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों, विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क को लगाने से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंध लगता है, द्वारा कमी नहीं आएगी। इसके प्रतिकूल

पाटनरोधी उपायों को लगाने के कारण पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ दूर किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता मिल सकेगी।

घ. निष्कर्ष

96. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा इस जांच परिणाम में दर्ज किए गए अनुसार, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के संबंध में तथा पाटन एवं क्षति के जारी रहने/उसके बार-बार होने/उसके और अधिक होने की संभावना तथा पाटन एवं परिणामी क्षति के जारी रहने की स्थिति का उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- (i) चीन जन गण से संबंधित उत्पाद का सतत पाटन हो रहा है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रहा है।
- (ii) आयात आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक कटौती कर रहे हैं और इस कारण कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ रही है।
- (iii) पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने और उसके बार-बार होने की संभावना है।

ड. सिफारिशें

97. तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए सोडियम नाइट्रेट के सभी आयातों, जो सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत आता है, पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जारी किए जाने की तिथि से संशोधित पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखा जाए। पाटनरोधी शुल्क वह राशि होगी जिसका उल्लेख नीचे दी गई तालिका के कॉलम संख्या 8 में किया गया है:

शुल्क तालिका

क्रम सं.	उप शीर्ष और टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पाक	निर्यातक	शुल्क राशि	माप की इकाई	करेंसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2834.1010	सोडियम नाइट्रेट	चीन जन गण	चीन जन गण	कोई अन्य	कोई अन्य	72.95	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन गण	चीन के अलावा कोई अन्य देश	कोई अन्य	कोई अन्य	72.95	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन गण	कोई अन्य	कोई अन्य	72.95	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

ढ. आगे की प्रक्रिया

98. केंद्र सरकार द्वारा इस अधिसूचना को स्वीकार किए जाने के बाद इसके विरुद्ध कोई भी अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जाएगी।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th July, 2017

(Final Findings)

Subject: Sunset Review of Anti-dumping duty imposed on the imports of Sodium Nitrite originating in or exported from China PR.

F. No. 15/06/2016/DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the Case

1. Whereas having regard to the above Act and the Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an antidumping investigation against import of Sodium Nitrite originating in or exported from China PR vide Notification No.39/1/99-DGAD on 4th November, 1999 and preliminary findings were issued by the Authority on 6th April, 2000. Provisional duties were imposed on 23rd May, 2000 vide notification no. 76/2000-Customs. The Authority notified final findings on 3rd November, 2000 recommending imposition of definitive duties on imports of Sodium Nitrite originating in and exported from China. The definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from the subject country were imposed by the Department of Revenue vide Customs Notification No. 147/2000 dated 19th December, 2000.
2. The imposition of duty has been reviewed from time to time and the second sunset review final finding was notified by the Authority vide Notification No. 15/4/2010 - DGAD dated 30th June, 2011 recommending continued imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. As per the recommendations of the Authority, the anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 76/2011-Customs dated 17th August, 2011.
3. After the mid-term review conducted at the behest of the petitioner requesting for change in the form of antidumping duty from the existing benchmark form to fixed form and enhancement in the quantum of anti-dumping duties, the Authority notified final findings recommending change in the form of anti-dumping duty vide Notification No. 15/2/2013-DGAD dated 15th October 2014. The anti-dumping duty was in force up to 16th August 2016 in accordance with Notification No. 76/2011-Customs dated 17th August, 2011 and the quantum of duty was modified in accordance with Notification No. 15/2/2013-DGAD dated 15th October 2014.
4. Whereas, in terms of the Act and the Rules, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.
5. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
6. And whereas, M/s. Deepak Nitrite Limited (hereinafter also referred to as “Petitioner” or “Applicant”) filed an application in the present case before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules for initiating sunset review of the anti-dumping duty on imports of Sodium Nitrite (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) and requested for extension of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
7. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant to justify initiation of sunset review investigation issued a public notice vide Notification No. 15/06/2016-DGAD dated 27th July, 2016

to examine whether the expiry of the said duties on the import of the above goods originating or exported from the subject country is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to 16th August, 2017, vide Notification No. 39/2016-Customs (ADD), dated 8th August, 2016.

8. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from China PR.

B. PROCEDURE

9. Procedure described below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:
 - i. The Authority notified the Embassies/Representatives of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - iv. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from China to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from China PR.
 - v. The Authority sent Exporter's Questionnaire and Market Economy Questionnaire to elicit relevant information to the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. Hebei Jingxing Bureau of Mines
 - b. Shanxi Jiaocheng Hongxing Chemical Co., Ltd.
 - c. Shandong Zhucheng Zhongtai Chemical Co. Ltd.
 - d. Qingdao Hengyuan Chemicals Co. Ltd.
 - e. China National & Chemicals I/E Corp.
 - f. Wuhan Chemicals I/E Corp.
 - g. Yunnan Provincial Chemicals I/E
 - h. Jiangmen Chemicals I/E Company of Guangdong
 - i. Kunming Imports & Export Corp.
 - j. China Hunan Chemicals Imp. & Exp. Corp.
 - k. Shanxi Jiaocheng Hongxing Chemical Co. Ltd.
 - l. Weifang Longstar Chemicals Inc.
 - vi. In response to the above notification, none of the exporters/producers has responded or submitted questionnaire responses.
 - vii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. Ahmadabad Chemicals, Ahmadabad
 - b. Asiatic Industries, Ahmadabad
 - c. Aries Dyechem Inds., Ahmadabad
 - d. Bakul Aromatics & Chemicals Limited, Mumbai
 - e. B.I. Mehta, Mumbai
 - f. Caffil Pvt. Ltd., Mumbai
 - g. Dintex Dyechem Limited, Ahmadabad
 - h. Dynamic Industries Limited, Ahmadabad
 - i. Enzel Chem (I) Pvt. Ltd., Mumbai
 - j. Farmson Pharmaceuticals, Vadodara

- k. Indocol Chem Ltd., Ahmadabad
 - l. Island Veer Chemie Pvt. Ltd., Hyderabad
 - m. Jansons Limited, Mumbai
 - n. Ketul Chem Pvt. Ltd., Mumbai
 - o. Metrochem Industries, Ahmadabad
 - p. Manish Chemicals, Ahmadabad
 - q. Parsin Chemicals Limited, Hyderabad
 - r. Prabava Exports, Hyderabad
 - s. Ravi Dyewear Co. Ltd., Mumbai
 - t. Roha Dyechem, Mumbai
 - u. Savakashi Dye – O – Fab, Ahmadabad
 - v. SU – Vi Chemicals Ltd., Solapur
 - w. Suven Pharmaceuticals Limited, Hyderabad
- viii. None of the importers of the subject goods has filed any questionnaire response in this matter. However, one of the importers of the subject goods, M/s. Sandeep Organics Ltd. has submitted a letter opposing the imposition of anti-dumping duty
- ix. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- x. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- xi. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xii. The Authority held an oral hearing on 27th September, 2016 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6), which was attended by the representatives of domestic industry only. The representatives of domestic industry who presented their views orally at the time of oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally at the time of oral hearing.
- xiii. Due to change in the incumbency of the Designated Authority and in line with the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the ATMA case, another oral hearing was conducted by the new Designated Authority on 6th February, 2017, which was attended by the representatives of domestic industry only. The representatives of domestic industry who presented their views orally at the time of oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally.
- xiv. On the spot verification of the data of the domestic industry was carried out to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this finding.
- xv. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is April, 2015 to March, 2016 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015 and the POI.
- xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this disclosure statement.
- xvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

- xix. In accordance with the Rules the Authority issued a disclosure statement containing all essential facts of the case on 21st June 2017 for the comments of the interested parties. The comments of the interested parties, to the extent they are relevant, have been addressed in this finding in appropriate places.
- xx. '***' in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxi. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.65.91 = 1 US\$.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 View of the Domestic industry

10. The views of the domestic industry are as follows:
- The present review investigation is a sunset investigation. The product involved in the original investigation and in the present sunset review investigation is Sodium Nitrite. The product under consideration in the present sunset review is the same as has been held by the Designated Authority in the original investigation. Sodium Nitrite is a white crystalline powder mostly used in pharmaceutical industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, heat transfer salts, meat processing, textiles etc.
 - Sodium Nitrite is classified under heading 2834.10 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.
 - There is no difference in the technology employed and the quality of the domestic and imported product. Present investigation is a review investigation. The Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the original investigation, which is relied upon.

C.2 Views of the other interested parties

11. None of the importers, consumers, exporters and any other interested party has filed any comment or submissions with regard to product under consideration, and like articles.

C.3 Examination by the Authority

12. The product under consideration is Sodium Nitrite. Sodium Nitrite is an oxidizing as well as reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceutical industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, heat transfer salts, meat processing, textiles etc. The subject goods are produced by using nitric acid obtained from nitrous oxide (nox gas) or ammonia at high temperature in presence of catalysts. The nitrous oxide is further absorbed in caustic soda/soda ash to get sodium nitrite. The product is odourless and soluble in water.
13. The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that in the original and subsequent review investigations, as per Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.
14. Sodium Nitrite is classified under heading 2834.1010 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.
15. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:
- "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*
16. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. The subject product produced by the domestic industry is comparable to the Product under consideration in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
17. Thus, the Authority holds that the subject product produced by the applicant domestic industry is like article to the Product under consideration exported from the subject country, in accordance with the AD Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**D.1 Views of the domestic industry**

18. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:
- The petition was filed by M/s Deepak Nitrite Ltd. as a domestic producer of the product under consideration and supported by M/s. Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd. (earlier known as Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Limited or PCPL). There are two more producers of the product in the country – National Fertilizers Ltd. and Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited.
 - Production of petitioner constitutes a major proportion in Indian Production (both after including and excluding support by PCPL) and therefore, the petitioner should be treated as “domestic industry” within the meaning of the Rules.
 - The petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and further, is not related to any exporter or producer of the subject goods in China or any importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).

D.2 Views of the other interested parties

19. None of the producers/exporters/importers/other interested parties have made any submissions in this regard.

D.3 Examination by the Authority

20. The application has been filed by M/s. Deepak Nitrite Limited and was supported by M/s. Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd. Further, there are two other producers of the subject goods apart from the applicant and supporter, namely, National Fertilizer Ltd. and Rashtriya Fertilizer and Chemicals Limited.
21. As per the Anti-dumping Rules, the Authority is required to examine whether (a) domestic producers expressly supporting the application account for more than twenty five percent of the total production of the like article by the domestic industry; and (b) the application is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. The applicant constitutes 88% of the total domestic production; and, with support of PCPL, the applicant constitutes 90% of the total Indian production. Further, the petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and, is not related to any exporter or producer of the subject goods in subject country or any importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).

INDIAN PRODUCTION

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Petitioner's Production	MT	100	131	155	187
Supporter's Production	MT	100	114	143	114
Petitioner including supporter	MT	100	131	154	184
Other Producers' Production	MT	100	131	155	187
Total Indian Production	MT	100	131	154	184
Share of Petitioner	%	100	100	100	101
Share of Supporter	%	100	87	93	62
Petitioner including Supporter	%	100	100	100	100
Share of Other Producers	%	100	100	100	101
Total	%	100	100	100	100

22. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the applicant satisfies the standing requirements and constitutes domestic industry under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

E. Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin

Normal Value under the Rules:

23. According to Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975, 'Normal Value' in relation to an article means:—

comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either—

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

E.1. Views of the Domestic industry

24. The domestic industry inter alia submitted as follows:
- One of the provisions of Accession protocol has expired on 11th December, 2016. The Designated Authority should proceed with present investigation considering Chinese producers as producers operating in non-market economy conditions due to reasons given below.
 - The investigation period considered by the Authority in the present case is April 2015 to March 2016 (12 months). The injury investigation period has been considered as the period 2012-13, 2013-14, 2014-15 and POI.
 - The purpose of fixation of POI is to consider a period when the existence of dumping causing injury is claimed and established. The date of determination is not relevant to the moot question of dumping causing injury to the domestic industry. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone should be considered relevant, appropriate and necessary for the purpose.
 - The Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies for the reason that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces. Para 8 to Annexure-I specifies the parameters which should be considered for grant of market economy status. This also implies that unless these conditions are not fulfilled/ satisfied, the Chinese costs and prices cannot be adopted.
 - The consideration of market economy status is based on parameters prevailing during investigation period. Since the reason for rejection of Chinese costs and prices is distortion in the costs and prices in China due to the factors listed in Para 8 to Annexure-I, petitioner submits that it is the investigation period that is relevant to decide consideration of Chinese producers as market economy companies.
 - Since Chinese companies have been denied market economy status for the reasons mentioned in Para 8 of Annexure-I till December, 2016, petitioner submits that the Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies till such time the investigation period includes the period specified in Accession Treaty protocol.

- g. In the context of rule 2(b), it is well established legal position that the imports by a domestic producer or its relationship with an exporter or importer are examined with reference to the investigation period. If POI alone is relevant for standing purposes, POI alone should be relevant for normal value determination.
- h. Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
- i. Normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. The petitioner has claimed consideration of normal value on the basis of cost of production in India duly adjusted.
- j. The dumping margin from China is not only significant, but also substantial, thus establishing existence of significant dumping of the product under consideration in India. The import volume of China has remained significant throughout the present injury period, despite anti-dumping duty in force.
- k. Considering the production capacities available with Chinese producers and their high export orientation, dumping would continue and even intensify in the event of cessation of anti-dumping duty.

E.2 Views of the interested parties

- 25. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has made any submissions with regard to normal value, export price and dumping margin.

E.3 Examination by the Authority

- 26. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - (i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph*

(a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

27. Article 15 implies that provisions of one of the subparagraph shall expire 15 years from date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired on 11th Dec., 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is April, 2015 to March, 2016. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the period of investigation, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
28. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

E.3.1 Examination of Market economy claims

29. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provides information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:
- The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
 - The exchange rate conversions are carried out at the market rate.
30. None of the exporter/producers have responded and filed questionnaire response. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and to proceed with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

E.3.2 Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

31. Normal value for the subject product imported from China PR into India has been constructed considering optimum consumption norms of the domestic industry for major raw materials and utilities, international prices of major raw materials (Caustic Soda and Ammonia), conversion cost, interest, SGA, etc. at the levels allowed for the domestic industry. 5% of cost of sales excluding interest has been allowed towards reasonable profit as per DGAD practice.

E.3.3 Determination of Export Price

32. None of the exporters from the subject country has provided any information giving details of export price. Therefore, the Authority has determined the export price for producers/exporters of China PR on the basis of the DGCI&S transaction wise data. Accordingly, the weighted average net export price at ex-factory level, in respect of all exporters from China PR has been determined after making due adjustments for Ocean Freight, Marine

Insurance, Commission, Bank Charges, Port Expenses and Inland Freight Charges on the basis of best available information and the same has been mentioned in the dumping margin table.

E.3.4 Determination of Dumping Margin

33. The export price to India (net of all the adjustments accepted by the Authority) has been compared with the normal value to determine dumping margin. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from subject country has been determined as provided in the table below:

Dumping Margin

Particular	Unit	POI
Normal Value	US\$/MT	***
Net Export Price	US\$/MT	***
Dumping Margin	US\$/MT	***
Dumping Margin	%	***
Dumping Margin	Range	30-40

F. INJURY AND CAUSAL LINK

F.1 Views of the Domestic industry

34. As regards injury and causal link, the domestic industry has submitted as follows :
- The demand/apparent consumption of the subject goods have increased over the injury period including the POI. Imports from subject country have remained significant despite anti-dumping duty, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India.
 - Landed price of imports (after including basic customs duties) have been significantly below the selling prices of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting. Under the circumstances, should the present anti-dumping duty cease, the imports would further undercut the prices of the domestic industry, which would prevent price increases to a significant degree.
 - The landed price of imports from China is materially below the cost of the domestic industry.
 - Market share of subject imports has declined as a result of anti dumping duty being in force. However, the market share of subject imports is still very significant.
 - The domestic industry enhanced its capacity during the injury period. The enhancement in capacity was fully justified by the present and potential demand for the product in the Country. Domestic sales volume has also increased over the injury period.
 - However, given the level of price undercutting, it is evident that the demand for the imported product would substantially increase in the event of cessation of anti dumping duties. This would directly imply decline in the demand of the domestic product, which is likely to result in decline in production of the domestic industry.
 - Performance of the domestic industry in terms of price parameters such as profits, cash profits and return on capital employed has also shown improvement in the POI. The domestic industry has come out from the situation of financial losses and has been making nominal profits after modification in the form of ADD from reference price basis to fixed form.
 - Presence of significant dumped imports would result in continued dumping leading to recurrence of injury in the absence of anti-dumping duty.
 - Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant.
 - Considering the capacities with the exporters in the subject country and their export orientation, there is likelihood of intensified imports in case existing anti-dumping duties is allowed to cease.
 - Resultantly, the domestic industry is likely to suffer injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - The anti-dumping duty is required to be continued. The form of measure is required to be kept as fixed quantum in terms of US\$.

F.2 Views of other interested parties

35. There are no co-operating exporters or importers. However, there is a letter from an interested party opposing the

investigations. Submissions made by this party are as under:

- i. The import price is directly related with crude, currency and freight.
- ii. Imports from China have reduced.
- iii. There is safeguard duty also.
- iv. There is cut throat competition between the domestic producers.
- v. There is less demand.
- vi. Domestic industries face high cost of production.
- vii. Domestic industries are making profit.
- viii. Domestic industries get government subsidy.
- ix. Import duties are higher.
- x. Current exchange rate of currency is higher.
- xi. Old duties should be re-worked.

F.3 Examination by the Authority

36. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Antidumping Rules and considering the submissions made by the other interested parties appropriately.
37. With regard the contention of other interested parties that import price of the product is directly related to crude, currency and freight; the Authority notes that the pricing of the product has no relationship with crude prices at all. Fluctuation in exchange rate of currency is a general phenomenon and not product specific and freight is also governed by inflationary effects.
38. As regards the presence of safeguard duty on the import of subject goods, the Authority notes that the safeguard duty imposed vide Notification No. 01/2014-Customs (SG) dated the 26th February, 2014 has already expired on 25th May, 2015 and there is no safeguard duty in force at present.
39. The injury analysis made by the Authority here under addresses the various other submissions made by the interested parties.
40. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
41. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
42. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of the Anti-dumping Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

43. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
44. For the examination of the impact of the imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.
45. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

F.3.1 Volume Effect of dumped imports and impact on domestic industry

a) Demand and Market Share

46. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Demand and Market Share

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Sales of Domestic Industry	<i>MT-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>136</i>	<i>159</i>	<i>194</i>
Captive Consumption of DI	<i>MT-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>92</i>	<i>131</i>
Sales of Other Indian Producers	<i>MT-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>127</i>	<i>152</i>	<i>168</i>
Subject Country-China PR	<i>MT-Indexed</i>	18,510	14,971	11,432	12,688
Country attracting ADD - EU	<i>MT-Indexed</i>	3,508	1,561	1,706	1,869
Other Countries	<i>MT-Indexed</i>	-	-	-	213
Demand including Captive	<i>MT-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>112</i>	<i>134</i>
Demand excluding Captive	<i>MT-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>113</i>	<i>134</i>
Market Share in Demand including Captive					
Domestic Industry	<i>%-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>127</i>	<i>142</i>	<i>146</i>
Captive Consumption of DI	<i>%-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>82</i>	<i>98</i>
Other Indian Producers	<i>%-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>118</i>	<i>135</i>	<i>125</i>
Subject Country-China PR	<i>%-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>75</i>	<i>55</i>	<i>51</i>
Country attracting ADD - EU	<i>%-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>41</i>	<i>43</i>	<i>40</i>
Other Countries	<i>%-Indexed</i>	-	-	-	<i>100</i>

47. The Authority notes that the demand for the product under consideration has increased in the POI as compared to base year as well as previous year, both including and excluding captive consumption by the domestic industry.
48. It is noted that the market share of the domestic industry, both including and excluding captive consumption, has increased; whereas the market share of the subject country has declined over the injury period, however, it is still very significant. The market share of imports from European Union, also attracting anti-dumping duty, has declined from 2013-14 and is very low.

b) Import volumes and share of subject country

49. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject country have been analysed as under:

Imports and Market Share

Import Volume	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Subject Country-China	MT	18,510	14,971	11,432	12,688
Country attracting ADD – EU	MT	3,508	1,561	1,706	1,869
Other Countries	MT	-	-	-	213
Total Imports	MT	22,018	16,532	13,138	14,770
Market Share in Imports					
Subject Country-China	%	84.07	90.56	87.02	85.90
Country attracting ADD – EU	%	15.93	9.44	12.98	12.65
Others	%	-	-	-	1.44
Total Imports	%	100.00	100.00	100.00	100.00
Production	<i>MT-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>131</i>	<i>154</i>	<i>184</i>
Demand including Captive	<i>MT-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>112</i>	<i>134</i>
Imports in relation to-					
Production	<i>%-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>62</i>	<i>40</i>	<i>37</i>
Consumption including Captive	<i>%-Indexed</i>	<i>100</i>	<i>75</i>	<i>55</i>	<i>51</i>

50. It is noted that the import volume from China has remained quite significant in both absolute terms throughout the injury period, despite anti dumping duty imposed. Though, the market share of subject imports in relation to production and consumption in India has declined over the injury period; it is still very significant.

F.3.2 Price Effect of dumped imports and impact on domestic industry**a) Price Undercutting**

51. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.
52. Price undercutting has been assessed by comparing the landed price of imports with the domestic selling price in India of the subject goods during the period of investigation. It would be seen that the landed price of imports without anti-dumping duty is lower than the selling price of the domestic industry and would result in significant price undercutting should the present anti-dumping duty be allowed to expire, as shown in the following table:

Price Undercutting

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Landed price of imports	Rs/MT	29,501	30,835	31,213	31,596
Net Selling Price	<i>Rs/MT-Indexed</i>	****	****	****	****
Price Undercutting	<i>Rs/MT-Indexed</i>	****	****	****	****
Price Undercutting	<i>%-Indexed</i>	****	****	****	****
Price Undercutting	Range	5-25%	5-25%	5-25%	5-25%

b) **Price Underselling**

53. The Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules.

Price Underselling

Particular	Rs./MT	US\$/MT
Exchange Rate		65.91
Non Injurious Price (NIP)	***	***
Landed Price	***	***
Injury Margin	***	***
Injury Margin-%	***	***
Injury Margin (Range)	10-20	10-20

54. It is seen that the landed price of the subject goods from China was significantly lower than the NIP determined for the domestic industry.

c) **Price suppression and depression effects of the dumped imports**

55. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Price Suppression/ Depression

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	96	96	94
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	101	112	116
Landed Price	Rs./MT	29,501	30,835	31,213	31,596
<i>Trend</i>	Index	100	105	106	107

56. It is seen that:

- i. The landed price of imports is significantly below the selling price of the domestic industry throughout the injury period including the period of investigation.
- ii. The landed price of imports is also significantly below the cost of sales of the domestic industry throughout the injury period including the period of investigation.
- iii. There is no price suppression or depression effect in the POI. However, the petitioner has claimed that in the absence of antidumping duty, subject imports would result in decline in the domestic prices leading to deterioration in the performance of the domestic industry.

F.3.3 Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry

57. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

58. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry are analysed herein below:

a) Actual and potential impact on Production, Capacity, Capacity utilization and Sales

59. The performance of the domestic industry with regard to production, capacity, capacity utilization and sales are as follows:

Production, Capacity, Capacity utilization and Sales

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Capacity Plant	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	135	146	161
Production - Plant	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	126	150	175
Production - PUC	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	131	155	187
Production - SNA	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	111	134	139
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	93	102	109
Domestic Sales excluding Captive consumption	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	136	159	194
Domestic sales including Captive consumption	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	134	153	189
Total Demand including Captive	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	108	112	134

60. The Authority notes that:

- i. The domestic industry enhanced its capacity over the injury period. The petitioner has claimed that such enhancement in capacity is fully justified by the present and potential demand for the product in the Country.
- ii. Production and sales volume of the domestic industry have also increased over the injury period.
- iii. Cessation of anti-dumping duties would result in increased importation of the imported product. This would directly imply decline in the demand of the domestic industry's product, which is likely to result in decline in production of the domestic industry.

b) Market Share

61. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Market share in Demand

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Market Share in Demand including Captive					
Domestic Industry	%-Indexed	100	127	142	146
Captive Consumption of DI	%-Indexed	100	103	82	98
Other Indian Producers	%-Indexed	100	118	135	125
Subject Country-China PR	%-Indexed	100	75	55	51
Country attracting ADD - EU	%-Indexed	100	41	43	40
Other Countries	%-Indexed	-	-	-	100

62. It is noted that the market share of the domestic industry, both including and excluding captive consumption, has increased; whereas the market share of the subject country has declined over the injury period, however, it is still very significant. Market share of imports from European Union, also attracting anti-dumping duty, has declined from 2013-14 and is very low.

c) Inventories

63. From the information given below, the Authority notes that the average inventory levels of the domestic industry significantly declined in the year 2014-15, and then have increased again in the period of investigation.

Inventories

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	98	27	53

d) Profits, return on investment and cash flow

64. Performance of the domestic industry with regard to profit, return on investment and cash flow is as follows:

Profitability, Profits, Cash Profits & Return on Investment

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	96	96	94
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	101	112	116
Profit / Loss	Rs./MT	***	***	***	***

<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>(100)</i>	<i>(66)</i>	<i>(11)</i>	<i>26</i>
Profit / Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>(100)</i>	<i>(91)</i>	<i>(18)</i>	<i>51</i>
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>(100)</i>	<i>(81)</i>	<i>13</i>	<i>104</i>
Profit before Interest & Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>(100)</i>	<i>(80)</i>	<i>15</i>	<i>101</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>(100)</i>	<i>(32)</i>	<i>5</i>	<i>31</i>

65. It is noted that the domestic industry was incurring losses upto 2014-15 on account of the presence of dumped imports in the domestic market. The domestic industry posted some nominal profits in the POI. Similarly, profit before interest, cash profit and return on investment have become positive in the POI, but the return on capital employed is much below the benchmark return of 22%.

e) **Productivity**

66. From the information given below, Productivity in terms of productivity per day as well as per employee has increased over the injury period, which is in line with the movement of production:

Productivity

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Productivity Per Employee	MT/Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>126</i>	<i>151</i>	<i>177</i>
Productivity Per Day	MT/Day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>131</i>	<i>155</i>	<i>187</i>

f) **Employment and wages**

67. It is noted from the table below that the employment with the domestic industry has increased over the injury period, except a decline in 2014-15. Wages paid have also increased, except a decline in 2013-14. The Authority notes that these parameters are dependent on a number of other parameters and not reflective of impact of dumping on the domestic industry.

Employment & Wages

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>102</i>	<i>106</i>
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>66</i>	<i>209</i>	<i>263</i>

g) **Growth**

68. The table below shows that the domestic industry has registered positive growth in terms of both volume and price parameters, such as, sales volume, production, capacity utilization, market share, profits, return on investment, cash profits etc. in the Period of Investigation, as an effect of anti-dumping duty being in place.

Growth

Growth % (Year by year)	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Production	MT	-	***	***	***
Domestic Sales	MT	-	***	***	***
Capacity Utilization	%	-	***	***	***
Market share	%	-	***	***	***
Profit/ Loss per unit	Rs./MT	-	***	***	***
Cash Profits	Rs. Lacs	-	***	***	***
Return on investment	%	-	***	***	***

h) Ability to raise Capital Investment

69. The domestic industry has enhanced capacity for production of product under consideration considering the present and potential demand for the product in the country. However, dumping has continued and would affect the domestic industry's ability to raise capital in case of cessation of anti-dumping duty.

i) Level of dumping & dumping margin

70. It is noted that imports from the subject country are entering the country at dumped prices and that the margin of dumping is significant.

j) Factors affecting domestic Prices

71. Both dumping margin and injury margin in the POI are positive and significant. Performance of the domestic industry has shown improvement in terms of production and sales volumes. Performance of the domestic industry has also shown improvement in terms of price parameters as the domestic industry has made some profits in the POI.

G. Other Known Factors & Causal Link

72. The Authority has examined other factors listed under the Antidumping Rules which could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

a) Volume and prices of imports from third countries:

73. The Authority notes that imports entering into the country from European Union are also attracting anti-dumping duty. Imports from all other countries are negligible and could not have caused claimed injury to the domestic industry.

b) Contraction of demand

74. There has been rise in demand of the product concerned over the injury period. Possible decline in demand could not have caused injury to the domestic industry.

c) Changes in the pattern of consumption

75. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry

d) Developments in technology

76. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

e) Conditions of competition and trade restrictive practices

77. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

f) Export performance of the domestic industry

78. The performance of the domestic industry and injury thereto has been examined with respect to the domestic performance to the extent possible. Possible deterioration in the export performance of the domestic industry is, therefore, not a possible cause of injury to the domestic industry.

g) Performance of other products produced and sold by the domestic industry

79. The performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

h) Productivity of the domestic industry

80. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has followed the same trend as production and increased. Deterioration in productivity is not a cause of injury to the domestic industry.
81. The known other factors listed above do not appear to have caused the injury determined. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has improved as a result of imposition of anti-dumping duty. However, significant volumes of imports from the subject country at dumped prices continue to enter the country.

H. Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

82. The Authority observed that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if the anti-dumping duties were to be allowed to expire even if there is no current injury. It is noted that the subject imports are still entering into the domestic market at dumped and injurious price.

H.1 Submissions made by the Domestic Industry

83. The domestic industry submitted as under in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:
- i. Significant dumping margin during POI establishes that dumping is likely to continue and intensify in the event of cessation of present anti-dumping duty. Dumping existed during the entire injury period. Also, high dumping margins existed during the previous anti-dumping investigations. This clearly leads to a conclusion that in case of cessation of antidumping duty, there is every likelihood of injury to the Domestic Industry..
 - ii. Anti-dumping and anti-subsidy measures are in force on exports of subject goods in US also. The volume of imports reported in the country increased after imposition of anti-dumping and anti-subsidy duty by US.
 - iii. Product under consideration continues to be exported to India at dumped prices from the subject country.
 - iv. Producers from subject country have significant capacity which establishes that in the event of cessation of duties, exports to India will intensify.
 - v. The exports of the product under consideration from subject country have been significant, both to India as well as to third countries. Further, the export prices have declined sharply.
 - vi. Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant.
 - vii. The price undercutting without prevailing anti-dumping duties is positive. The return on investment and cash profit would be significantly negative in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - viii. The import prices are materially below the selling price of the domestic industry. The consumers would therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product. In case of cessation of anti-dumping duty, the domestic industry shall have to reduce their selling price to compete with dumped imports, forcing them to sell even below the cost of sales, leading to severe price injury.
 - ix. The foreign producers are intensely focused on exports. In the event of cessation of anti-dumping duty, these exporters are likely to increase their exports to India at dumped prices.
 - x. The Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of low priced imports from the subject country in the market shall definitely cause an adverse impact on the domestic industry. So dumping and consequent injury to the domestic industry is likely to continue/increase in the event of cessation of anti dumping duty.

H.2 Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

84. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

H.3 Examination of the Authority

85. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules. Clause (vii) of Annexure II to the rules provides for four factors which are required to be taken into consideration, viz.:

(a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation

86. Considering the dumping margin determined by the Authority in the previous investigations and the dumping margin now assessed, it is quite evident that the exports were continued to be made at dumped prices and are likely to continue with cessation of anti-dumping duties. Despite the imposition of anti-dumping duty, the imports of the subject goods from the subject country still continue at dumped prices. Further, the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of cessation of anti-dumping duty, given the level of price undercutting effects from the imports of subject goods from China PR.

(b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports

87. This parameter for ascertaining the threat of material injury requires evaluation of existing surplus capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market. Domestic industry has claimed that the producers in subject countries are already faced with significant surplus capacities. Further, these producers are exporting the product to a large number of countries, a very significant proportion of which is being exported at a price below the prices in respect of India, thus showing likelihood of diversion of these exports to India in the event of withdrawal of Anti-Dumping duty. Interested parties have not provided any verifiable evidence and information with regard to existing surplus capacities, and consequent likelihood/possibility of increased dumped exports to Indian market.

(c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports

88. The prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the Indian market. Therefore, in case of expiry of duty, exporters from the subject country would further channelize their output in the Indian market in view of significant capacity with them. This clearly would result in likelihood of injury to the domestic industry. Imports from subject country are likely to undercut the prices of the domestic industry.

(d) inventories of the article being investigated

89. Inventories of the Domestic industry have reduced compared to the base year.

I. Magnitude of Injury and Injury Margin

90. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the imports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

Injury Margin

Particulars	US\$/MT
Exchange Rate	65.91
Non Injurious Price (NIP)	***
Landed Price	***
Injury Margin	***

Injury Margin-%	***
Injury Margin (Range)	10-20

J. POST-DISCLOSURE COMMENTS

J.1 Submissions made by the Domestic Industry

91. The petitioner inter alia has submitted as follows: –

- a. The product under consideration is Sodium Nitrite. Since the customs classification is indicative only, the Designated Authority may kindly specify the same in duty table and that the product under consideration should attract duty regardless of the customs classifications under which goods are being cleared by the importers.
- b. Both dumping margin and injury margin in the POI are positive.
- c. Performance of the domestic industry has shown improvement in terms of volume as well as price parameters as a result of continued imposition of anti-dumping duty and more because of change in the form of anti-dumping duty from benchmark to fixed form.
- d. The domestic industry has not suffered continued injury, but dumping has continued.
- e. Likelihood of intensified dumping and consequent injury is imminent as significant dumping was found by the Authority in previous investigations, volume of imports has remained significant since inception and even in present investigations, Chinese producers have significant surplus capacities as against Indian demand, Chinese product is attracting anti-dumping and anti-subsidy duty in US since long, exports to other countries are at dumping and injurious prices.
- f. Indian market being highly price sensitive, cessation of anti-dumping duty would result in flooding of Indian market with dumped goods undercutting the domestic prices and causing material injury to the domestic industry.
- g. While the petitioner does not agree with the requirement of Annexure-III itself, without prejudice, at least, the Authority may kindly re-determine the non-injurious price in accordance with Annexure III to the Rules.
- h. The Authority may kindly consider extension of existing anti-dumping duties as there is no material injury. No injury implies that calculation of injury margin is not required and same duties should be extended.
- i. Anti-dumping duty may be continued in existing quantum and fixed form expressed in terms of US\$.

J.2 Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

92. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

J.3 Examination of the Authority

93. The Authority notes that post-disclosure comments/submission made by the domestic industry are mostly reiterations of earlier submissions, which have already been examined suitably and adequately and properly addressed in the disclosure statement or relevant paras of the present finding. The authority further considers as follows with regard to fresh issues raised by the domestic industry
- i. As regards the submissions of the domestic industry concerning determination of non-injurious price (NIP), the Authority notes that the detailed guidelines for computation of NIP is laid down under Annexure III of the Anti-dumping Rules and the same has been adopted while determining NIP in the present investigation.
 - ii. As regards the submission of the domestic industry concerning continuation of the existing quantum and form of duty, the Authority notes that injury margin as well as dumping margin is positive in the present case. The mandate of the Designated Authority is to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend adequate quantum of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the quantum and form of the anti-dumping measures is decided by taking in to consideration the facts of a case.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

94. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the

domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

95. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

L. CONCLUSIONS

96. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/ recurrence/ intensification of dumping and injury, the Authority concludes that:
- There is continued dumping of the product concerned from China PR, causing injury to the domestic industry.
 - Imports are significantly undercutting and underselling the prices of the domestic industry.
 - Cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation and recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

M. RECOMMENDATIONS

97. Accordingly, the Authority recommends that revised anti-dumping duties be continued to be imposed from the date of issue of notification by the Central Government on all imports of Sodium Nitrite falling under chapter 28 of Custom Tariff Classification Act 1975, originating in or exported from China PR. The anti-dumping duty shall be the amount mentioned in Column No. 8 of the following table:

Duty Table

SN	Sub-heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2834.1010	Sodium Nitrite	China PR	China PR	Any	Any	72.95	MT	US\$
2	-Do-	-Do-	China PR	Any country Other than China	Any	Any	72.95	MT	US\$
3	-Do-	-Do-	Any Country other than China	China PR	Any	Any	72.95	MT	US\$

N. Further Procedures

98. An appeal against this notification, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority